RAJYA SABHA

Monday, The 28th July, 1997/6 Shravana, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** *in the chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Financial Liabilities of ECL

*61. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Eastern Coalfields Limited, a subsidiary of the Coal India Limited, is potentially sick with rising debts;

(b) if so, what are the financial liabilities of the company till date;

(c) what are the circumstances leading to the company's sickness; and

(d) what measures have been taken to revive the company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The financial liabilities of Eastern Coalfields Limited (ECL) as on 31.3.1997 are as under:

Liabilities	As on 31.3.97 (Rs. in crores) (Provisional)
1. Paid-up capital	1039.00
2. Reserves	9.32
3. (i) Secured loans	36.83
(ii) Unsecured loans	2080.96
4. Current liabilities	1560.59

(c) The circumstances leading to the sickness of ECL are:—

(i) There are 11 areas producing 39.94% of the total production of ECL but engaging 68.83% of the company's manpower. About 80% of the average annual loss of ECL is caused by these 11 areas.

(ii) The capacity utilisation and per capita productivity (output per man shift) in ECL are very low as compared to the other subsidiaries of Coal India Limited.

(iii) Underground mines of the country, in general, have much lower productivity than the opencast mines. Proportion of underground production to the total production in ECL is high. The requirement of sand stowing in the underground mines of ECL adds to the cost of production. Majority of the underground mines are very old and a large number of them are being worked manually.

(iv) Many underground mines of ECL are having geo-mining problems like steep and multiple seams, occurrence of fire and water-logged old working.

(v) The size of the mine determines the economics of production. By and large due to the presence of various geo-mining problems, even after re-organisation of some of the mines, the average size of the mines in ECL is small.

(d) In February 1996 the Government waived the overdue normal interest of Coal India Limited upto 31.3.92 of Rs. 891.75 crores and the penal interest accruing thereon since 1.4.95 upto 31.3.96. Consequently, CIL waived a corresponding interest of Rs. 389 crores due to it from ECL. In March, 1996 the Government decided to deregulate the prices of coking coal and A, B & C grades of non-coking coal. In March 1997 the Government have deregulated the prices of hard coke, soft coke and D grade of non-coking coal.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Madam, at the outset, I would like to pay compliments to the Minister that she has taken a lot of pains in answering the

question. The answer supplied by her is quite informative. The Eastern Coalfields Ltd.—a subsidiary of the Coal India Ltd.—is a chronic sick company, which owes to the Central and State Governments, I believe, over Rs. 65,000 crores against sales-tax, royalty, cess etc. Its total accumulated loss, I believe, is about Rs. 850 crores. It is quite possible that there may be some hidden losses also. The main reason for losses appears to be the surplus man-power. My first supplementary question is: (a) What have been the losses suffered by the Eastern Coalfields Ltd. in the last three years, that is, 1994-95, 1995-96 & 1996-97? (b) What is the total man-power employed in the Eastern Coalfields Ltd.? and (c) How much of this man-power is surplus in these coalfields?

श्रीमती कान्ति सिंह: उपसभापति महोदया, जैसा कि माननीय सांसद् महोदय ने प्रश्न किया है, मुझे बहुत ही खुशी है कि इन्होंने हमारे जो ई॰सी॰एल॰ की विचारणीय स्थिति है उस पर इन्होंने गंभीरता से ख्याल रखा है। इसमें ई॰सी॰एल॰ की वित्तीय स्थिति जो है वह 1993-94 में 1,850 करोड़, 1994-95 में 1,962 करोड़ और साथ ही 1995-96 में 1,766 करोड़ की है और 1996-97 में 2,117.79 करोड़ का है। जहां तक मैनपॉवर का सवाल है अभी टोटल 1996-97 में 1,58,251 है जिसको कि इसके अंत में 1996-97 में 1,54,443 मैनपॉवर हो जायेंगे उसमें है आपके प्राकृतिक क्षति से 1,771, वी॰आर॰एस॰ से 2400 और लैस इनटेक से 354, अभी फिलहाल 1996-97 में हमारे यहां जैसा कि बताया गया 1,54,434 है और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं से 2001-02 में 1,35,185 हमारे यहां मैनपॉवर होंगे तो इससे हम घाटे को कम कर सकेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Madam, I come to the second supplementary. Unless immediate measures are taken to control the expenses and to increase the productivity, that is, the production per person, things are not likely to improve in the ECL. The productivity in USA, UK, etc. is very high as compared to India. I believe, it is almost 30 times, what it is per person in India. Therefore, Madam, drastic steps are to be taken for rationalising man-power by voluntary retirement scheme and by proper mechanisation. I understand, as I have just learnt from the hon. Minister, that to achieve the target of reduction as far as man-power is concerned, a beginning has been made and the situation will be reviewed from time to time.

My second supplementary is what the figure of production per annum, per employee in India is; and how this figure compares with other leading countries like USA, UK, Russia and China. Madam, I have taken only four countries—USA, UK, Russia and China. How does the Government propose to improve the productivity per person? Thirdly, what are the other measures that the Government propose to adopt to bring down the losses?

श्रीमती कान्ति सिंह: उपसभापति महोदया, इस घाटे को कम करने के लिए हमने नई-नई परियोजनाओं को लिया है जिस में झंझरा, जे॰के॰ नगर, सतग्राम, कालीदासपुर, सर्पी, अमृतनगर, चित्रा पश्चिम ओपन कास्ट, सोनपुर, जांबाद, कोट्टाडीह, बंसरा, राजमहल (इस की एक्सपेंशन तब की जाएगी जब एन॰टी॰पी॰सी॰ कास्ट प्लस बेसिस पर कोयला लेने को तैयार हो जाए)। महोदया, इन सभी परियोजनाओं के वित्त पोषण में करीब 600 करोड़ रु॰ की लागत आएगी एवं इस का स्रोत भी मैनेजमेंट द्वारा तय कर लिया गया है और इस पंचवर्षीय योजना में कुल वित्त करीब 870 करोड़ रुपए की जरूरत है।

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, what is she reading out? Let us know.

श्रीमती कान्ति सिंह: इस में सुधार के लिए हम ने वर्ष 1997-98 के लिए एक कार्य-नीति बनायी है जिस में क्षेत्रवार अधिकतम उत्पादन, एस॰डी॰एल॰/एल॰एच॰डी॰ के उत्पादन में सुधार लाए जाने हेतु विशेष अभियान, यंत्रीकृत लांगवाल फेसेज के उत्पादन में सुधार लाए जाने हेतु विशेष बल दिया जाना, कोयला उत्पादन को कम करने के साथ-साथ राजमहल ओपन कास्ट से ऊपरी मलबा हटाने पर बल देना चूंकि एन॰टी॰पी॰सी॰ कोयले के वचनबद्ध मात्रा उठाने में असफल रही है।

...(व्यवधान)...

SHRI VAYALAR RAVI: Has the supplementary been given in advance? (*Interruptions*) It is her official note.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: बिड़ला जी ने उन्हें लिखकर दे दिया है।

श्रीमती कान्ति सिंह: मैं आप को जवाब दे रही हूं तो आप को बहुत खराब लग रहा है...

उपसभापति: यह बात नहीं है।

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदया, मैं डिटेल में उस का जवाब दे रही हूं।

उपसभापति: वह सवाल अलग है, डिटेल अलग है। उन्होंने 4 देशों के बारे में पूछा है कि उन का "पर-कैपिटा प्रोडक्शन" कितना है और हमारे देश में कितना है और उसे उस लेवल तक लाने के लिए आप क्या करेंगी? यह सवाल है, उस का जवाब आप दीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदया, जैसा कि उन्होंने पूछा कि पुनरोद्धार के लिए हम कितनी जल्दी और क्या व्यवस्था कर रहे हैं इसलिए मैं उस बारे में डिटेल रूप से बता रही हूं। सब से पहले तो हमारे यहां ई०सी०एल० में प्रति व्यक्ति क्षमता कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सब्सिडरीज से काफी कम है। ई०सी०एल० में वर्ष 97 में यह 0.83 है जब कि सी०आई०एल० में यह आंकड़ा 1.86 है।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: I would like the hon. Minister to send the reply after consulting her department. Let her send the reply later on.

SHRI VAYALAR RAVI: That is better.

श्रीमती कान्ति सिंह: अगर माननीय सांसद चाहते हैं तो मैं जवाब भेज दूंगी।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: मंत्री महोदया, राष्ट्रीयकरण को 24 साल गुजर गए। मैं आप का ध्यान नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में आप के ही आंकड़ों के आधार पर 12.8 करोड़ टन कोयला नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश को जितनी जरूरत है उस से कम है और दसवीं योजना में कोयले की आपूर्ति 10.2 करोड़ टन से कम है। उतना कोयला देश का बाहर से मंगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप की इकाइयां बीमार हो रही हैं। इस के बावजूद कि कोयले की कीमत आप निर्धारित करती हैं, कोयले का ग्रेड आप निर्धारित करती हैं और कोयला उद्योग पर आप का एकाधिकार है। तो देश का फारेन एक्सचेंज जोकि हर साल 30 हजार करोड़ रुपए तक केवल कोयला खरीदने के लिए व्यय होगा, उस को बचाने के लिए आप का मंत्रालय क्या कर रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्रीमती कान्ति सिंह: उपसभापति महोदया, उन सभी को बचाने के लिए हम नई-नई योजनाओं को ला रहे हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। उस के साथ-साथ वर्ष 93 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में परिवर्तन कर के कैप्टिव माइंस को लाए हैं। कटिंग माइंस के द्वारा भी हम लोग खनन कर के कोयला उत्पादन करेंगे और अभी जैसा कि बताया गया कि कोयला बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है और फारेन में पैसा जा रहा है, उस के लिए हम एक नया बिल लाने जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम माईनिंग ब्लाक ऑफर करेंगे जिससे कि हमारी डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है, उस को पूरा करेंगे।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: महोदया, मैंने जो आंकड़े दिए हैं, वे जिन तथ्यों को मंत्री महोदया ने कहा है उस के बावजूद के आंकड़े हैं। अगर यह नहीं करेंगे तो और बड़ा गैप होगा, शॉर्टेज होगी। तो यह आंकड़े उस के बाद के हैं। मेरा प्रश्न यह था कि आप क्या करने जा रही हैं? देश एक भयावह स्थिति में जाने वाला है कोयले के मामले में और कोयला मंत्रालय सोया हुआ है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्रीमती कान्ति सिंह: उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि जो इनका सवाल है, कोयले की स्थिति को सुधारने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं और मैं इन्फॉरमेशन के लिए यह बताना चाहती हूं कि हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पावर प्लांट में 15 दिनों का कोयला एडवांस में पड़ा हुआ है और कई ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज हैं, जो और कोयला लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यह पहली दफा हुआ है।

SHRI JIBON ROY: I don't agree that either the manpower or the underground mining has been mainly responsible for the sickness of the ECIL. I feel that the policy pursued by the previous Government has been the main reason.

I wish to know from the hon. Minister whether the new Government has reviewed the policy of the previous Government. She has said in her answer that the underground mining is the main problem. But the fact is that before

nationalisation the total quantum of the underground mining was 75 per cent of the total mining, but now it is only 25 per cent of the total mining.

So far as the workers' point is concerned, utter neglect of the underground mining is one of the main reasons for the downfall of the ECIL. The ECIL is located mainly in town areas. You have closed the entire production through the underground mining system. You are not bringing in plant and machinery for the underground mining system. Therefore, the ECIL is bound to fail. The second part is...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jibon Roy, what is your question? Is it an information or a question?

SHRI JIBON ROY: Most of the project taken up by the World Bank has failed. Part (a) of my question is whether the Government has assessed and reviewed the coal mining policy of the previous Government.

Part (b) of my question is whether you have dispelled the fears of the labour, did they discussed the matter with trade union leaders to make it viable. These are the two questions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't put two questions.

SHRI JIBON ROY: They are parts (a) and (b).

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is nothing like (a) and (b). It becomes two.

श्रीमती कान्ति सिंहः उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पुरानी नीतियों का हमने पुनरावलोकन किया है या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि जितने हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनसे हम समय-समय पर अपनी पालिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहती हूं कि आगे भी हम जो पालिसी लाने जा रहे हैं, उसमें भी हम सारी ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे।

अब अंडरग्राउंड माईंस को सुधारने का जहां तक सवाल है, अंडरग्राउंड माईंस में उच्च तकनीक लगाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जैसे कि लौंग वाल इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी एच०ई०एम०एम० लौंग वाल मशीनरी है, उसके ओरिजिनल कलपुर्जों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करना, एच०डी०एल० एवं एस०एल०डी० की उत्पादकता को बढ़ाना और इस तरह से लौंग वाल इक्विपमेंट्स की उत्पादकता बढ़ाना और बेल्टिंग से कोयले की निकासी की शुरुआत करना, यह सब हम कर रहे हैं। पी०एस०एल०डब्ल्यू० यानी पावर सपोर्ट लौंग वाल को भी हम चालू कर रहे हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः उपसभापति महोदया, पिछले 24 सालों में कितने सुधार हुए हैं, उनके संबंध में मंत्री महोदया ने बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं और उसके ऊपर प्रबंधन कर रहे हैं। महोदया, 24 या 25 साल पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था। उन्होंने अपने उत्तर में यह भी कहा और जिसको बिरला जी ने सराहा कि वहां जो काम करने वाले लोग हैं, उनको समय-समय पर कम किया जा रहा है और कम किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत मैं मंत्री महोदया से दो बातें पूछना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का "क" भाग यह है कि...**(व्यवधान)**

उपसभापतिः चतुर्वेदी जी, कृपया एक ही प्रश्न पूछ लीजिए क्योंकि मेरे पास दूसरे लोगों के नाम भी हैं। आप अगर "क" और "ख" भाग में जाएंगे तो मुश्किल होगी।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, जैसा आप कहेंगी। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि कितनी कमेटियां पिछले साल में जो उन्होंने चार मुद्दे बताए हैं और जिसके निराकरण के लिए ही राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितनी कमेटियों की नियुक्त हुई, उन्होंने क्या सुझाव दिए और आपने उनके अनुसार कितनी कार्रवाई की है, क्योंकि इसमें मुद्दा यह भी है कि वाटर लॉगेड ओल्ड वर्किंग ऑकरेंस आफ फायर जिससे कि बहुत सी वहां पर वारदातें और घटनाएं भी हो चुकी हैं और ये कम हो जाती अगर आपने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की होती। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की हैं?

श्रीमती कान्ति सिंहः उपसभापति महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कितनी कमेटी हमने बनाई हैं, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। मैं बाद में भिजवा दूंगी। सुधार करने के लिए बहुत सारे माईंस में हम काम कर रहे हैं। इन सभी से हम अंडरग्राउंड माईंस के बचाव के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और खास तौर पर यह जो घाटे में हमारी वहां की माईंस चल रही है उसके पुनरूद्धार के लिए योजना बना रहे है। ई०सी०एल० में 11

ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम्पनी को सबसे ज्यादा घाटा होता है। 1997-98 में पांच परियोजनाओं से फायदा होने की भी संभावना है जो यह है—बंकोला, कजोडा, तेंदा, झांझरा एवं सतग्राम। अन्य इलाके जैसे कि सौधपुर, श्रीपुर, पांडवेश्वर, मुगमा, सलानपुर, सीतारामपुर की पुनरूद्धार योजना अभी बनाई जा रही है।

उपसभापति: आप कमेटी की डिटेल्स भिजवा दीजिएगा। उन्होंने यह सवाल पूछा है कि जो कमेटी बनी है उनकी रिपोर्ट क्या आई। आप बाद में भिजवा दीजिएगा।

श्रीमती कान्ति सिंह: मैं भिजवा दूंगी।

Use of Naphtha as Fuel for Power Plant

*62. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to encourage power plants which use Naphtha as fuel to run these units;

(b) if so, how many such units are permitted in the private sector throughout the country, State-wise;

(c) what steps are being taken to discontinue the licenses already issued to some private firms by State Governments to start such units; and

(d) whether Government will frame a policy on the use of fuel by power plants in private sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) It had been decided that in order to establish additional power generation capacity that could materialise in the short run. Power projects based on liquid fuels, including naphtha would be permitted.

(b) Details are given in the Statement-I (*See* below)

(c) Fuel linkages are being given for power projects based on the State Government's recommendations of specific projects within the ceiling capacity allotted to each State.

(d) There already exists a policy which permits private sector units to set up power plants based on fuel oils like heavy petroleum stock. Low sulphur heavy stock have furnace oil, furnare oil naphtha and natural gas.

Statement-I

State-wise Naphtha Based Private Sector Power Projects

Sl. No.	State	Number of Naphtha based power projects
1.	Rajasthan	9
2.	Maharashtra	5
3.	Uttar Pradesh	8
4.	Tamil Nadu	6
5.	Andhra Pradesh	9
6.	Karnataka	16
7.	Haryana	3
8.	Madhya Pradesh	4
9.	Gujarat	13
10.	Kerala	3
11.	Pondicherry	2
12.	Goa	1

SHRI JOHN F. FERDNANDES: Madam, before I ask my supplementary, I have to make a small printing correction in my question. In part (a) the word "encourage" should be read as "discourage"

THE DEPUTY CHAIRMAN: What was there in your original question?

SHRI JOHN F. FERNANDES: That was in my original question. "...to discourage..." and not "to encourage..."

I have got the answer from the Government. Madam, we know the projection of the Government in the Ninth Five-Year Plan. There is a shortfall